साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कॉर्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every...

वर्ष : 10, अंक : 27 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 5 फरवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

2035 के लिए अब तक महज सात देशों ने साझा किए हैं अपने जलवायु लक्ष्य

नई दिल्ली। 2035 के लिए अब तक महज सात देशों ने ही अपनी जलवायु योजनाएं साझा की हैं, जबकि इसकी समय-सीमा अगले महीने है। इससे पता चलता है कि वे जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट (आईआईईडी) द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक कहीं न कहीं यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में राजनीतिक नेतृत्व की कमी को भी दर्शाता है।

गौरतलब है कि पेरिस समझौते में शामिल देशों को हर पांच साल में जलवायु परिवर्तन से संबंधित अपनी अपडेटेड योजनाएं प्रस्तुत करनी होती हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) कहा जाता है। बता दें कि इसे तहत अगला लक्ष्य 10 फरवरी 2025 तक प्रस्तुत करना है।

ये लक्ष्य इस बात को आधार प्रदान करते हैं कि प्रत्येक देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या कुछ कार्रवाई करेंगे। पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि को डेढ़ डिग्री सेल्सियस पर सीमित रखना है। 10 फरवरी की समय सीमा में अब महज दो सप्ताह का वक्त बचा है, लेकिन अब तक पेरिस समझौते में शामिल सिर्फ तीन फीसदी देशों ने ही अपने एनडीसी सबमिट किए हैं। वहीं अमेरिका पहले ही पेरिस समझौते से पीछे हटने की अपनी मंशा की घोषणा कर चुका है। ब तक जिन सात देशों ने अपने अपडेट एनडीसी प्रस्तुत किए हैं, उनमें अमेरिका, ब्राजील, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात, स्विटजरलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। ब्राजील इस

वर्ष के अंत में कॉप30 की मेजबानी करेगा। यूनाइटेड किंगडम ने अजरबैजान में संपन्न हुए कॉप29 सम्मेलन के दौरान अपने 2035 के लक्ष्यों की घोषणा कर दी थी और इसे 30 जनवरी को प्रस्तुत कर दिया गया है। इसी तरह स्विटजरलैंड ने भी 2031 से 2035 के लिए अपनी योजना 29 जनवरी 2025 को अपनी योजना प्रस्तुत कर दी है। न्यूजीलैंड ने भी आज 31 जनवरी 2025 को 2035 के लिए नए जलवायु लक्ष्य साझा कर दिए हैं। न्यूजीलैंड ने इन नए लक्ष्यों में 2035 तक अपने उत्सर्जन में 2005 के स्तर से 51-55 फीसदी की कटौती करने का वादा किया है। आईआईईडी में जलवायु विशेषज्ञ कैमिला मोर ने इस बारे में प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि, दुनिया तेजी से गर्म हो रही है, ऐसे में जल्द से जल्द साहसिक कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।

पारंपरिक जापानी स्थापत्य और बौद्ध संस्कृति का प्रतीक है किंकाकूजी स्वर्ण मंदिर -मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने जापान के ऐतिहासिक किंकाकूजी स्वर्ण मंदिर का किया भ्रमण

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जापान यात्रा क्योटो स्थित विश्व प्रसिद्ध किंकाकूजी (स्वर्ण मंदिर) का भ्रमण किया। पारंपरिक जापानी स्थापत्य और बौद्ध संस्कृति का प्रतीक यह मंदिर अपनी सोने की परतों से ढंकी भव्य संरचना और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का अवलोकन किया और जापानी संस्कृति में इसकी ऐतिहासिक महत्ता को करीब से समझा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंदिर के सामने स्थित क्योकाची तालाब के किनारे कुछ समय बिताया, जहां मंदिर की झलक पानी में प्रतिबिंबित होकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें सिर्फ स्थापत्य कला का उदाहरण नहीं होतीं, बल्कि वे एक सभ्यता की आत्मा को दर्शाती हैं। जापान ने अपनी संस्कृति को सहेजने का जो प्रयास किया है, वह प्रशंसनीय मुख्यमंत्री डॉ. यादव की जापान यात्रा सिर्फ सांस्कृतिक आदान-प्रदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने जापानी धरोहर संरक्षण, पर्यटन विकास और वास्तुकला के नवाचारों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश भी अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है और जापान से इस दिशा में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की जापान यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और औद्योगिक संबंधों को और अधिक सशक्त बनाना है। भ्रमण के दौरान उन्होंने जापान की परंपरागत और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखने की नीति को भी सराहा।

आर्थिक नुकसान से बचने के लिए ऐसे हो भारतीय राज्यों में आपदाओं की तैयारी

नई दिल्ली। बदलती जलवायु की वजह से आपदाएं और चरम मौसम की घटनाएं, जैसे कि लू या हीटवेव, सूखा और जंगल की आग में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र, बुनियादी ढांचे और लोगों की बस्तियों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने इन आपदाओं के कारण भारत के 25 राज्यों में होने वाले आर्थिक नुकसान का पता लगाया है।

पिछले 23 सालों की अवधि को शामिल करने वाले इस अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इन प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि किस तरह से राज्यों के बजट को सालाना गंभीर रूप से असर डालती है। यह शोध आपदा की बेहतर तैयारी और आर्थिक सुरक्षा के लिए समाधान भी देता है, साथ ही ऐसे संकटों से होने वाले आर्थिक नुकसान के नतीजों को कम करने में मदद करने के लिए एक रोडमैप भी प्रदान करता है। शोध पत्र के हवाले से शोधकर्ता ने कहा कि आपदा के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान, मौतों की संख्या और प्रभावित लोगों की संख्या के मूल्यांकन के आधार पर नुकसान का अनुमान लगाया जाता है। ये मूल्यांकन अक्सर सही नहीं होते हैं। शोध में चक्रवात की ताकत और बाढ़ की गंभीरता को सटीकता से मापने के लिए मौसम और भौगोलिक स्रोतों के आंकड़ों का उपयोग किया गया। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में प्रकाशित शोध के मुताबिक, इस जानकारी के आधार पर शोधकर्ताओं ने एक आपदा तीव्रता सूचकांक (डीआईआई) बनाया, जिससे यह साफ हो गया कि सभी तरह की आपदाओं का निष्पक्ष तरीके से निपटारा किया जाए। यह विधि विसंगतियों और पूर्वाग्रहों से बचती है और आपदा प्रभावों की स्पष्ट तस्वीर देती है, खासकर बाढ़ और चक्रवातों के लिए, जिनके कारण अध्ययन अवधि के दौरान भारत में आपदा से संबंधित 80 फीसदी तक नुकसान देखा गया। अध्ययन में बताया गया है कि इसमें पैनल वेक्टर ऑटो रिग्रेशन (वीएआर) नामक सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि एक साल से लेकर अगले कुछ सालों तक राजस्व और व्यय एक दूसरे पर किस तरह असर डालते हैं। यह मॉडल राज्यों के बीच अंतरों को ध्यान में रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि पिछली आर्थिक स्थितियां आपदा की गंभीरता के माप को गलत तरीके से प्रभावित न करें, जिससे आपदाओं के वित्तीय प्रभावों का अध्ययन करने का एक विश्वसनीय तरीका हासिल होता है। अध्ययन से पता चलता है कि आपदाएं प्रभावित राज्यों पर भारी वित्तीय बोझ डालती हैं, क्योंकि इससे उनका खर्चा बढ़ जाता है और साथ ही उनका राजस्व भी कम हो जाता है। जिसके कारण राज्य तत्काल राहत प्रयासों जैसे कि निकासी, चिकित्सा सहायता, भोजन और आश्रय के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करते हैं। सरकार सड़कों, पुलों और घरों जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में भी निवेश करती है। क्योंकि इन आपदाओं के कारण कृषि, व्यापार और व्यावसायिक को चलाने में अक्सर रुकावट आती है, इसलिए इन क्षेत्रों से कर संग्रह और आय में भी कमी आती है। अध्ययन एक ऐसे चक्र पर प्रकाश डालता है जिसमें व्यय में वृद्धि और राजस्व में गिरावट के कारण बजट में भारी घाटा होता है। शोध में कहा गया कि आपदा तीव्रता सूचकांक (डीआईआई) से पता चलता है कि आपदाएं राज्यों पर अलग-अलग तरीके से असर डालती हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे कम आपदा-प्रवण राज्य, जो सूखे और कभी-कभी बाढ़ का सामना करते हैं, अपने स्वयं के संसाधनों से राहत का प्रबंधन कर सकते हैं और उनकों आर्थिक नुकसान कम होता हैं। आपदा की तीव्रता लोगों की आय या उत्पादन को प्रभावित करने के लिए काफी नहीं है, इसलिए कर या बिना-कर के राजस्व में कोई कमी नहीं है। दूसरी ओर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे आपदा-प्रवण तटीय राज्य, जो अक्सर चक्रवात और बाढ़ का सामना करते हैं, में खर्च और राजस्व घाटा अधिक होता है। नतीजतन, उन्हें अक्सर ऋण जैसे बाहरी वित्तपोषण पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे राज्य का कर्ज बढ़ता है और अन्य विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करना मुश्किल हो जाता है। शोध में सुझाव देते हुए कहा गया है कि राज्यों को पूर्व चेतावनी प्रणाली, चक्रवात आश्रयों और बुनियादी ढांचे में निवेश करने और टिकाऊ भूमि उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है जो जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव को कम कर सकता है। साथ ही आपदाओं से निपटने के लिए लंबे समय तक होने वाले खर्चों को कम कर सकता है।ोध के मुताबिक, कई राज्यों ने पहले ही इसे लागू कर लिया है, तमिलनाडु ने उन्नत चक्रवात निगरानी प्रणाली स्थापित की है, केरल ने जलवायु-अनुकूल शहरी नियोजन को अपनाया है और ओडिशा और कई अन्य ने जलवायु-संबंधी खर्च के लिए बजट ट्रैकिंग शुरू की है। जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में लगातार बढ़ोतरी जारी है, इसलिए शोध पत्र में शोधकर्ताओं के हवाले से चेतावनी दी गई है कि भविष्य में भारतीय राज्यों को और भी बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सुझाए गए उपायों को अपनाकर भारत लंबे समय तक आर्थिक खतरों को कम किया जा सकता है। सतत विकास, आपदा के खतरों को कम करने के लिए दुनिया भर में आम सहमति बनाने, अध्ययन में आपदा जोखिम वित्तपोषण (डीआरएफ) के अनुरूप राष्ट्रीय नीतियों को बनाने और चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास किया है। यह सरकारों के लिए तत्काल आपदा प्रतिक्रिया को राजकोषीय नीतियों के प्रबंधन के साथ-साथ प्रभावित आबादी की तत्काल जरूरतों का प्रबंधन करने पर जोर देता है। यह जीवन और बुनियादी ढांचे की रक्षा कर सकता है और एक मजबूत, अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

मैं भी बाघ'' और हम हैं बदलाव'' थीम पर

भोपाल वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल के समन्वय से मैं भी बाघ'' और हम हैं बदलाव'' थीम पर प्रशिक्षण-सह-जागरूकता शिविर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में आयोजित किया गया। शिविर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिसरोद के 120 छात्र-छात्राओं और 5 शिक्षक-शिक्षिकाओं ने सहभागिता की। शिविर में सम्मिलित हुए प्रत्येक छात्र-छात्रा को अनुभूति बुक, अनुभूति बैग, कैप, ब्रोशर दिये गये। छात्र-छात्राओं को जलीय पक्षी, स्थलीय पक्षी, तितली प्रजाति, गिद्ध कुंजी के ब्रोशर भी दिये गये। मास्टर ट्रेनर एवं नवीन प्रेरकों द्वारा पक्षी दर्शन, वन्य-जीव दर्शन, प्रकृति पथ-भ्रमण स्थल पर विद्यमान वानिकी गतिविधियों की जानकारी दी गयी। शिविर में शामिल सहभागियों ने फूड बैग, फूड चैन जैसे खेल खेलकर वन, वन्य-जीव एवं पर्यावरण से संबंधित रोचक गतिविधियों में हिस्सा लिया। इसमें सहभागिता करने वालों की जिज्ञासाओं को भी शांत किया गया। रेस्क्यू टीम द्वारा छात्र-छात्राओं को वन्य-जीवों को कैसे रेस्क्यू किया जाता है, के संबंध में रेस्क्यू वाहन के माध्यम से रेस्क्यू करने संबंधी जानकारी दी गयी। इसका सभी सहभागियों ने भरपूर आनंद लिया। अनुभूति कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर के रूप में सेवानिवृत्त उप वन संरक्षक डॉ. एस.आर. वाघमारे और वन विहार के सहायक संचालक श्री एस.के. सिन्हा एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

फरवरी 2025 में बढ़ेगी गर्मी, गेहूं सहित अन्य फसलों को हो सकता है नुकसान- मौसम विभाग की चेतावनी

नई दिल्ली। मौसम विभाग ने आउटलुक में किसानों को सुझाव देते हुए कहा है कि फसलों पर कम बारिश और बढ़ते तापमान के बुरे प्रभाव को कम करने तथा फसल के विकास को बनाए रखने के लिए बीच-बीच में हल्की सिंचाई करें। मौसम विभाग के द्वारा जारी फरवरी महीने के आउटलुक के मुताबिक, पूरे देश में सामान्य से कम, यानी एलपीए के 81 फीसदी से कम बारिश होने की आशंका जताई गई है। फरवरी 2025 के दौरान देश के अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान के सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं, सिवाय उत्तर-पश्चिम भारत और भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों, जहां न्यूनतम तापमान के सामान्य रहने की संभावना जताई गई है। वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में शीत लहर वाले दिनों की संख्या सामान्य से कम रहने का पूर्वानुमान है।

फरवरी के महीने में देश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान के सामान्य से अधिक रहने की आशंका है, वहीं, पश्चिम मध्य भारत और भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों, जहां अधिकतम तापमान के सामान्य से कम रहने की संभावना है जताई गई है। फरवरी में सामान्य से कम बारिश और सामान्य से अधिक तापमान का खेती पर गहरा असर पड़ने का अंदेशा जताया गया है। उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में सामान्य से कम बारिश और उच्च तापमान की वजह से गेहूं जैसी खड़ी फसलों पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। गेहूं की फसल अभी फूलने और दाने आने के चरण में हैं। सरसों और चना जैसी फसलें भी समय से पहले पक सकती हैं, जाहिर है समय से पहले पकने से पैदावार व गुणवत्ता दोनों में कमी आने की आशंका है। जबकि, सेब और अन्य शीतोष्ण गुठलीदार फलों जैसी बागवानी फसलों में बढ़ते तापमान के कारण समय से पहले कली टूटने की आशंका जाहिर की गई है और जल्दी फूल आ सकते हैं, जिसकी वजह से फलों की गुणवत्ता खराब हो सकती है, पैदावार पर भारी प्रभाव तथा किसानों को नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने आउटलुक में किसानों को सुझाव देते हुए कहा है कि फसलों पर कम बारिश और बढ़ते तापमान के बुरे प्रभाव को कम करने तथा फसल के विकास को बनाए रखने के लिए बीच-बीच में हल्की सिंचाई करें। हालांकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अपेक्षित सामान्य या सामान्य से कम अधिकतम तापमान के कारण, फसलों पर शीत लहर का बुरा प्रभाव न के बराबर पड़ने की संभावना है। फरवरी 2025 के दौरान उत्तर भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, तथा लद्दाख में बारिश के सामान्य से कम, यानी लंबी अवधि के औसत (एलपीए) के 78 फीसदी से होने के आसार हैं। फरवरी 2025 में देश में शीत लहर वाले दिनों की संख्या के सामान्य से कम रहने का पूर्वानुमान है। देश के अधिकांश हिस्सों में शीत लहर वाले दिन सामान्य सीमा के भीतर रहने की संभावना है। हालांकि उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में शीत लहर वाले दिनों की संख्या के सामान्य से कम रहने की का अनुमान है। वर्तमान में भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में ला नीना की कमजोर स्थितियां जारी हैं और मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान (एसएसटी) सामान्य से कम है। नवीनतम एमएमसीएफएस पूर्वानुमान से पता चलता है कि कमजोर ला नीना की स्थितियां अप्रैल 2025 तक बनी रहने का पूर्वानुमान है, जिसके बाद ईएनएसओ-तटस्थ स्थिति आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं, हिंद महासागर पर तटस्थ हिंद महासागर डिपोल (आईओडी) स्थितियां बनी हुई हैं और नवीनतम एमएमसीएफएस पूर्वानुमान के मुताबिक, तटस्थ आईओडी स्थितियां अगले दो महीनों तक जारी रहने की संभावना है।

जल जीवन मिशन पर फोकस लेकिन बीते वित्त वर्ष में करीब 70 फीसदी हुई कमी

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में अपना आठवां बजट पेश करते हुए सरकार के महात्वाकांक्षी जल जीवन मिशन की डेडलाइन 2028 तक के लिए बढा दिया है। उन्होंने दावा किया कि 2019 से लेकर अब तक 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पेय जल की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जो कुल ग्रामीण आबादी का 80 फीसदी है।

यानी सरकार के बजट भाषण के मुताबिक अगले चार सालों में बची हुई 20 फीसदी ग्रामीण आबादी तक नल से पेयजल की सुविधा प्रदान की जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव भी किया जाएगा। हालांकि, यह जानना जरूरी है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 70162.90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया जबकि संशोधित अनुमान महज 29916.8 करोड़ रुपए का ही रहा। यानी बजट में 67.36 फीसदी की कमी कर दी गई। हालांकि, इस बार के केंद्रीय बजट आंकड़ों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 67000.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बीते वित्त वर्ष 2024-25 के मुकाबले इस बार जल जीवन मिशन के लिए किया गया प्रावधान 195 फीसदी ज्यादा लग सकता है लेकिन बीते वित्त वर्ष की तरह असल में साल के अंत में वास्तविक बजट क्या होगा, यह सवाल बना रहेगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि जल जीवन मिशन का मुख्य ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता और जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में पाइप से जल आपूर्ति योजना के ऑपरेशन एंड मेंटनेंस पर होगा। इसके लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पृथक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया जाएगा ताकि इसकी निरंतरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा को तय किया जा सके। बजट भाषण में सार्वधिक ध्यान जिस तरफ था वह ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की तरफ ही था। वहीं केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 74226.02 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें करीब 90 फीसदी बजट का हिस्सा जल जीवन मिशन के लिए ही है। यानी ग्रामीण पेयजल को छोड़कर महज 10 फीसदी बजट अन्य ड्रिंकिंग सैनिटेशन कार्यों के लिए है। बजट के लेखा-जोखा की पड़ताल करने पर यह पता चलता है कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिग वाटर सैनिटेशन के हिस्से में दूसरा बड़ा मद ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के लिए है।

नशामुक्ति की दिशा में मोहन सरकार ने बढ़ाया प्रभावी कदम

प्रमुख तीर्थ नगरों से होगी शुरूआत

भोपाल लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 300 वीं जयंती पर मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने खरगोन जिले में अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में कैबिनेट कर ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसे पूरे प्रदेश में सराहा गया। निर्णय था, प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों एवं ग्रामपंचायतों में शराबबंदी का। इसी दिन मोहन सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि पुण्य सलिला माँ नर्मदा के तट के दोनों किनारे 5 किलोमीटर की परिधि में शराबबंदी पूर्ववत लागू रहेगी। यह दिन इस लिये भी मध्यप्रदेश के इतिहास में स्मरणीय बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने महिलाओं के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन को भी स्वीकृत कर लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशामुक्ति की दिशा में उठाया गया। यह कदम जन-आस्था और धार्मिक दृष्टि से श्रृद्धा के 19 नगरीय क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों में प्रभावशाली होगा। मंत्रि-परिषद ने जिन धार्मिक स्थान पर शराब बंदी का निर्णय लिया उसमें एक नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें हैं। जिन प्रमुख पवित्र नगरों में शराबबंदी लागू की जा रही है उनमें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक, महेश्वर, ओरछा रामराजा मंदिर क्षेत्र, ओंकारेश्वर, मंडला में सतधारा क्षेत्र, मुलताई में ताप्ती उद्गम क्षेत्र, पीतांबरा देवीपीठ दतिया, जबलपुर भेड़ाघाट क्षेत्र, चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर, सांची, मंडलेश्वर, वान्द्रावान, खजुराहो, नलखेड़ा, पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र मंदसौर, बरमान घाट और पन्ना शामिल हैं। नये वित्तीय वर्ष से इन सभी क्षेत्र में शराब की दुकानें नहीं

रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिये वकास के साथ विरासत का मंत्र दिया है। हमारी सरकार 13 दिसम्बर 2023 को कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही इस सूत्र पर काम कर रही है। विरासत की रक्षा के लिये जितना महत्वपूर्ण भवनों, ऐतिहासिक स्थलों और साँस्कृतिक प्रसंगों को सहेजना होता है उतना ही महत्वपूर्ण समाज जीवन की विशिष्टताओं को सहेजना है जिससे आने वाली पीढ़ियाँ संस्कारवान बन सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थ केवल धार्मिक क्षेत्र ही नहीं होते, उन्हें समाज निर्माण का केन्द्र माना गया है। वहाँ का वातावरण सात्विक होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी उज्जैन सिहंस्थ के दृष्टिगत हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार विकास कार्यों के साथ विरासत सहेजने की दिशा में काम कर रही है। इस निर्णय से पहले कृष्ण पाथेय निर्माण करने, राम पथ गमन के विकास का काम तेज करने, वर्ष 2028 के सिंहस्थ की तैयारी आरंभ करने, खुले में माँस बिक्री प्रतिबंधित करने और ध्वनि विस्तारकों को सीमित करने जैसे निर्णय लिये गये हैं। इसके साथ पाठ्यक्रम में महापुरुषों का जीवन चरित्र जोड़ने की पहल की गई है, जिससे, नई पीढ़ी को संकल्पशीलता की प्रेरणा मिले। मध्यप्रदेश सरकार का यह निर्णय भारतीय सांस्कृतिक विरासत की उस जीवन शैली की ओर है जिसमें शाकाहार, सात्विकता और नशामुक्त जीवन शैली को आदर्श माना गया है। मांस-मदिरा मुक्त जीवन शैली को देवों और मनुष्यता का प्रतीक माना जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार आस्था केन्द्रों के माध्यम से ऐसा वातावरण बनाना चाहती है, जिससे समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। प्रत्येक स्थान की अपनी मौलिक ऊर्जा होती है। प्रत्येक स्थान अथवा क्षेत्र की अपनी विशिष्ट ऊर्जा होती है। इसे हम धरती के विभिन्न भागों के निवासियों की जीवन शैली और मानसिकता से समझ सकते हैं। भारतीय मनीषियों ने ऐसे स्थानों में तीर्थ क्षेत्रों का चयन किया जो सकारात्मक ऊर्जा का केन्द्र हैं, जिससे व्यक्ति वहाँ जाकर क्षोभ से मुक्त होकर उत्साह के साथ लौटे जिससे उसके कर्म कर्तव्य भी आदर्श हों।

'जलवायु छाया'

एक नई और बढ़ती हुई अवधारणा है 'जलवायु छाया', जिसका मतलब कार्बन फुटप्रिंट से कहीं अधिक है। हमारे प्रतिदिन के क्रियाकलापों में, चाहे वह यात्रा हो, खाना खाना हो, वस्त्र खरीदना हो या डिजिटल सेवाओं का उपयोग करना, हर कदम का जलवायु पर असर होता है। इस छाया को मापना और इसे बेहतर बनाना पर्यावरणीय स्थिरता के लिए जरूरी है। यह उन सभी तरीकों को समाहित करता है जिनसे व्यक्ति, कंपनियां और सरकारें जलवायु पर प्रभाव डालती हैं। इसमें न केवल ऊर्जा उपयोग और उत्सर्जन शामिल होते हैं, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला, जल संसाधनों का उपयोग, भूमि का प्रबंधन और अन्य गतिविधियों का पर्यावरणीय प्रभाव भी शामिल होता है। स्थायी भविष्य की दिशा में जलवायु छाया बढ़ाने में सौर, पवन और जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना शामिल है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला और तेल भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। अगर सरकारें और कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें, तो यह जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। लोगों को यह समझना आवश्यक है कि उनके छोटे-छोटे कदम, जैसे कि ऊर्जा की बचत, पौधरोपण और प्लास्टिक का कम उपयोग, जलवायु छाया बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में स्थायी पद्धतियों का उपयोग करना और जल संसाधनों का प्रबंधन जलवायु छाया बढ़ाने में प्रमुख योगदान दे सकता है। जैविक खेती, जलसंचय तकनीक, और फसल चक्र में विविधता लाने से मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है और जलवायु पर दबाव कम होता है। बड़े कॉर्पोरेट्स और उद्योगों का जलवायु छाया पर भारी प्रभाव पड़ता है। कंपनियां अब कार्बन न्यूट्रल बनने की दिशा में काम कर रही हैं। इसका अर्थ है कि जितना कार्बन उत्सर्जन वे करती हैं, उतना ही उत्सर्जन ऑफसेट करती हैं, यानी वातावरण से हटाती हैं। उद्योगों को हरित उत्पादन प्रक्रियाओं और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना चाहिए। इससे उत्पादों का पर्यावरणीय प्रभाव कम होगा और जलवायु छाया बढ़ेगी। सरकार की नीतियां और कार्यक्रम जलवायु छाया को बढ़ाने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारें विभिन्न नीतिगत उपायों के जरिए कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित कर सकती हैं और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे सकती हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भी हम जलवायु छाया को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें छोटे-छोटे कदम उठाने होंगे। जैसे- ऊर्जा की बचत के लिए घरों में एलईडी बल्बों का उपयोग करें। प्लास्टिक का उपयोग कम करें और रिसाइक्लिंग को बढ़ावा दें। पौधे लगाएं और अधिक से अधिक हरित क्षेत्रों को संरक्षित करें। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और निजी वाहनों का कम से कम प्रयोग करें। जलवायु छाया बढ़ाना एक व्यापक प्रयास है जो सरकारों, उद्योगों और आम नागरिकों की सामूहिक भागीदारी की मांग करता है। इसके लिए न केवल नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकता है, बल्कि सामूहिक जागरूकता और छोटे-छोटे कदम भी जरूरी हैं।

इसरो को झटका -एनवीएस-02 नेविगेशन सेटेलाइट में आई तकनीकी खराबी

नई दिल्ली । इसरो से आज यानी सोमवार तड़के 100वें मिशन में तकनीकी खराबी आने की बात सामने आ रही है। 29 जनवरी को इसरो ने एनवीएस-02 नेविगेशन सेटेलाइट मिशन को लॉन्च किया था। इस सेटेलाइट को जीएसएलवी-एफ15 के जरिए लॉन्च किया था। इसरो ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि सेटेलाइट में तकनीकी खराबी के कारण आगे बढ़ाने की प्रक्रिया रुक गई है। ये श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसरो का 100वां प्रक्षेपण है।

इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष यान में लगे 'थ्रस्टर्स' के काम नहीं करने से एनवीएस-02 उपग्रह को वांछित कक्षा में स्थापित करने की कोशिश सफल नहीं हो सकी। इसरो ने कहा कि लॉन्च के बाद सेटेलाइट में लगे सौर पैनल को सफलतापूर्वक तैनात किया था। बिजली उत्पादन नाममात्र है। ग्राउंड स्टेशन के साथ कम्यूनिकेशन सिस्टम स्थापित हो गया है, लेकिन सेटेलाइट कक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जा सका क्योंकि थ्रस्टर्स को फायर करने के लिए ऑक्सीडाइज़र को प्रवेश करने वाले वाल्व नहीं खुले।इसरो सूत्रों का कहना है कि सेटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने के बाद वह फायर करने में विफल रहा। सेटेलाइट सिस्टम एक दम हेल्दी है और वह मौजूदा वक्त में अण्डाकार कक्षा में है। अण्डाकार कक्षा में नेविगेशन के लिए उपग्रह का उपयोग करने के लिए वैकल्पिक मिशन रणनीतियों पर काम कर रहा है। इसरो का एनवीएस-02 सेटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर एक अण्डाकार कक्षा में स्थापित करने का इरादा था। बताया था कि इसके सबसे दूर का बिंदू 37,500 किमी रहेगा जबकि पेरीजी यानी निकटतम बिंदू 170 किमी पर होगा। 29 जनवरी को जीएसएलवी द्वारा बहुत सटीक इंजेक्शन ने सेटेलाइट को एक ऐसी कक्षा में स्थापित किया था जो लक्ष्य किए गए अपोजी से 74 किमी और पेरीजी से 0.5 किमी दूर पर था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (आईएनएसपीएसीई) के अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका ने लॉन्च के वक्त कहा था कि यह मिशन भारत की अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन की दशकों पुरानी विरासत और हमारे भविष्य के संकल्प को भी दर्शाता है। निजी प्रक्षेपणों के साथ-साथ, मैं अगले पांच सालों में अगले 100 प्रक्षेपणों को देखने के लिए उत्सुक हूं। हैदराबाद स्थित अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सीएमडी सुब्बा राव ने कहा था कि 100वां प्रक्षेपण न केवल इसरो की तकनीकी क्षमता का उत्सव है, बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमताओं का भी प्रदर्शित करता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008